बहुसंख्यकवादी राजनैतिक एजेंडा और भारतीय मुसलमान

राम पुनियानी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने पार्टी की जो नयी राष्ट्रीय कार्यकारणी घोषित की है, उसमें एक जानेमाने पसमांदा मुसलमान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को तेरह उपाध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया है. भाजपा की केरल इकाई के एक नेता पी. अब्दुलकुट्टी, जो पिछली कार्यकारिणी के सदस्य थे, को भी पुनार्निर्युक्ति दी गयी है. इस समय भाजपा का फोकस राष्ट्रीय स्तर पर पसमांदा मुसलमानों को महत्व देने पर है. पसमांदा सबसे पिछड़े मुसलमान है, जिनमें से अधिकांश दलित या ओबीसी हैं. वे समाज और मुस्लिम समुदाय में सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सबसे निचले पायदान पर हैं.

भाजपा अलग-अलग दौर में मुसलमानों के विशिष्ट तबकों में अपनी पैठ बनाने का प्रयास करती रही है. इस समय, पार्टी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है परन्तु पूर्व में उसने मुसलमानों को राज्यपाल (सिकंदर बख्त) और केंद्रीय मंत्री (शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी) नियुक्त किया है. मोदी हाल में एक बोहरा मस्जिद में पहुंचे जहाँ उन्होंने घोषणा की कि बोहरा उनकी परिवार का हिस्सा हैं. वे समय-समय पर अजमेर में ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़ाते रहे हैं.

पिछले कुछ समय से भाजपा पसमांदा मुसलमानों को लुभाने में लगी हुई है. इस साल, उत्तर प्रदेश में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में उसने कुछ पसमांदा मुसलमानों को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनमें से कुछ चुनाव जीते भी हैं. सन 2022 की जुलाई में भाजपा की एक अहम बैठक हैदराबाद में हुई थी. उसमें मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे पसमांदा मुसलमानों में अपनी पैठ बनाएं. उन्होंने यह भी कहा था कि मुस्लिम समुदाय एकसार नहीं है और पसमांदा, मुसलमानों का पिछड़ा तबका है. तभी से पसमांदा मुसलमानों को पार्टी की छतरी तले लाने के प्रयास चल रहे हैं.

भाजपा इस समुदाय को लुभाने के लिए यह कह रही है कि मोदी की नीतियां किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करतीं और पसमांदा मुसलमान भी मोदी सरकार की 'विकास योजनाओं' के उतने ही 'लाभार्थी' हैं जितने अन्य समुदाय. इस बीच कई जानेमाने मुसलमानों, जिनमें पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी शामिल थे, ने आरएसएस मुखिया मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखकर उनसे 'मेलमिलाप संवाद' के लिए समय माँगा. एक महीने के इंतजार के बाद उन्हें संघ प्रमुख के दरबार में आने की इज़ाज़त मिली.

इन प्रमुख मुसलमानों ने भागवत से 'मुस्लिम समुदाय के प्रति बढ़ती नफरत' और उनके साथ 'बुलडोज़र न्याय' पर बात की. यह भी कहा कि मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी कहा जाता है. भागवत का जवाब था कि हिन्दू भी गौहत्या और उन्हें काफिर कहे जाने से आहत महसूस करते हैं. इस 'संवाद' के बाद, आरएसएस के प्रमुख नेताओं, जिनमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुखिया इन्द्रेश कुमार, कृष्ण गोपाल और राम लाल शामिल थे, ने 22 सितम्बर 2022 को आल इंडिया इमाम आर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इल्यासी से मुलाकात की. इल्यासी ने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत से सांप्रदायिक सौहार्द में वृद्धि होगी.

इन संवादों का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ा है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती है. संघ परिवार के कई लेखक जिनमें राम माधव और पूर्व भाजपा नेता सुधीन्द्र कुलकर्णी शामिल है, ने सितम्बर 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भागवत के तीन व्याख्यानों के बाद तर्क दिया था कि आरएसएस बदल रहा है. भागवत ने कहा था कि हिन्दुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है आदि, आदि.

सच क्या है? सच यह है कि किसी भी राजनैतिक संगठन, भले ही वह खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता हो, के दावे का सच इससे जाहिर होता कि वह और उसके साथी संगठन किस तरह की राजनीति करते हैं और कौनसे मुद्दे उठाते हैं. भागवत स्वयं भी गौमांस और गौमाता का मसला उठाते रहे हैं. पिछले कुछ दशकों में यह एक भावनात्मक मुद्दा बन गया और इसके चलते न केवल मुसलमानों को अत्याचार और दमन का शिकार होना पड़ रहा है वरन ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गयी है. ऐसा क्यों है कि बीफ को हिंदी पट्टी में तो मुद्दा बनाया जा रहा है पर केरल, पूर्वोत्तर और गोवा में नहीं? ऐसा क्यों है कि किरण रिजुजू जैसे नेता खुलकर कहते हैं कि बीफ उनके खानपान का हिस्सा है? और ऐसा क्यों है कि अटलबिहारी वाजपेयी जैसे शीर्ष नेता बीफ खा सकते हैं?

सच यह है कि नफरत की राजनीति के सबसे बड़े शिकार पसमांदा ही हैं. अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत संघ की शाखाओं और शिशुमंदिरों और भाजपा के आईटी सेल द्वारा फैलाई जा रही है. नफरत से हिंसा फैलती है, हिंसा से ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण के कारण मुसलमान अपने-अपने मोहल्लों में सिमटते जा रहे हैं. पसमांदा मुसलमान साम्प्रदायिक हिंसा से सबसे अधिक पीड़ित हैं.

पिछले कुछ समय से बुलडोजर भी न्याय करने लगे हैं. संघ और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह कानून के मुताबिक है. जाहिर है कि यह सच नहीं है. इसके अलावा संघ का शीर्षतम नेतृत्व यह प्रचार कर रहा है कि मुसलमान बहुसंख्यक बन जाएंगे. हम सबको याद है कि कुरैशी ने अपनी पुस्तक 'पापुलेशन मिथ' मोहन भागवत को भेंट की थी. इसमें इस मिथक को तर्कसंगत ढंग से गलत सिद्ध किया गया. कुछ समय पहले भागवत ने भी अपरोक्ष रूप से यह कहा था कि देश की मुस्लिम आबादी अन्य समुदायों की तुलना में तेजी से बढ रही है.

नफरत फैलाने के नए-नए तरीके ढूंढ़े जा रहे हैं. कोरोना जेहाद की बातें हुई हैं और अब टमाटर की कीमतों में बढ़ोत्तरी के लिए भी मुसलमानों को दोषी ठहराया जा रहा है. कुछ समय पहले हमें बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए यूसीसी लागू की जाएगी. मजे की बात यह है कि यूसीसी का पहला मसविदा भी तैयार नहीं है. इसके पहले एनआरसी और सीएए के नाम पर मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने के प्रयास हुए थे. इसके विरोध में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आईं थीं और शाहीन बाग पर ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. इस बीच हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को गहरा करने वाली कई फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें कश्मीर फाईल्स, केरेला स्टोरी और 72 हूरें शामिल हैं. सरसंघचालक से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इन फिल्मों की तारीफ की और भाजपा नेताओं ने थोक में इनके टिकट खरीदकर लोगों को दिखाईं ताकि नफरत के जहर को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके.

कुल मिलाकर संघ का मूल चरित्र वही है जो पिछले सौ सालों से रहा है. भाषा और शब्द बदल गए हैं परंतु हिन्दू राज का एजेंडा वही है. पसमांदा मुसलमानों को केवल चुनावों में लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह मुसलमानों को बांटने की रणनीति का हिस्सा भी है. सच यह है कि चाहे पसमांदा हो या अशरफ - सभी मुसलमान संघ और भाजपा की नीतियों के शिकार बन रहे हैं. पसमांदा मुसलमानों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन एक नए प्रहसन से ज्यादा कुछ नहीं है. **(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया; लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)**

इससे पहले कि मुल्क भूल जाए वह दर्दनाक हादसा !

श्रवण गर्ग

मणिपुर के पहले संसद में बहस शायद जयपुर-मुंबई सुपर फ़ास्ट एक्सप्रेस में घटी त्रासदी पर होना चाहिए और प्रधानमंत्री से जवाब भी माँगा जाना चाहिए ! चलती ट्रेन में हुई त्रासदी और उसके मुख्य पात्र द्वारा उसकी ही गोली के शिकार हुए चार लोगों में से एक के शव पास खड़े होकर दी गई नफ़रती स्पीच पर अगर बहस हो जाए तो फिर मणिपुर, मोनू मानेसर और हरिद्वार पर भी अपने आप हो जाएगी !

चेतन सिंह अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहा। हो सकता है इस नाम का उस शख़्सियत से कोई ताल्लुक़ ही स्थापित नहीं हो पाए जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात सूरत स्टेशन पर अपने बॉस और अन्य सहयोगियों के साथ एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए ट्रेन पर सवार हुआ था। एस्कॉर्ट ड्यूटी बोलें तो यात्रियों की सुरक्षा के लिये ट्रेन में चलने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (आरपीएफ़) का अमला।

कांस्टेबल चेतन सिंह या तो खुद ही भूल गया होगा कि उसने क्या अपराध किया है या उसके परिवार सहित जो ताक़तें उसे मानसिक रूप से विचलित, विक्षिप्त अथवा अवसाद-पीड़ित साबित करने में जुटी हैं वे उसकी याददाश्त का गुम हो जाना सिद्ध कर देंगी ! 'गज़नी' फ़िल्म के नायक संजय सिंहानिया को ऐसी बीमारी होती है जिसमें वह पंद्रह मिनिट से ज़्यादा पुरानी बात भूल जाता है। व्यक्ति ही नहीं , हुकूमतें भी जब सत्ता की असुरक्षा या किन्हीं अन्य कारणों से अवसाद अथवा विक्षिप्तता की शिकार हो जाती हैं तो बड़े-बड़े हत्याकांडों, आगज़नियों और मानवीय चीत्कारों को पलक झपकते ही भूल जातीं हैं।

मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कांस्टेबल को घटना के बाद जब मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया तो घटना का प्रस्तुत विवरण उस जानकारी से कुछ भिन्न था जो जनता के बीच और मीडिया में प्रचारित है। मसलन, बताया गया है कि सांप्रदायिक नफ़रत से भरे उसके भाषण और उससे संबद्ध धाराओं का आरोपों के विवरण में कथित तौर पर उल्लेख नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक़, सुनवाई के दौरान मीडिया की उपस्थिति भी प्रतिबंधित थी।

चेतन सिंह अब किसी का भी नाम हो सकता है ! जैसे हरिद्वार, हाशिमपुरा ,हाथरस, कश्मीर घाटी या मणिपुर। उसे किसी हुकूमत का नाम या प्रतीक भी माना जा सकता है। उसके द्वारा दी गई जिस 'हेट स्पीच' का उल्लेख बहु-प्रचारित वीडियो में है उसमें नया कुछ भी नहीं है। हरिद्वार की 'धर्म संसद' में दो साल पहले दिये गये नफ़रती भाषणों से उसके कहे का मिलान किया जा सकता है। प्रकाशित विवरणों के मुताबिक़, आर पी एफ़ के कांस्टेबल द्वारा हत्याकांड के बाद कुछ इस प्रकार की स्पीच दी गई थी =' अगर वोट देना है ,तो मैं कहता हूँ, मोदी और योगी ये दोनों हैं और आपके ठाकरे !'

हरिद्वार की 'धर्म संसद' में उपस्थित सैंकड़ों साधु-संतों के द्वारा हिंदू समुदाय का आह्वान किया गया था कि अल्पसंख्यकों की समाप्ति के लिए शस्त्र उठाना होगा। एक ऐसे समय जब हरियाणा के कुछ शहर सांप्रदायिक हिंसा से झुलस रहे थे, एक राष्ट्रीय चैनल का एंकर जर्मनी में हिटलर द्वारा किए गये यहूदियों के नरसंहार की तर्ज़ पर ही 'समस्या' के 'फाइनल सोल्यूशन' की वकालत कर रहा था ! समस्या यानी ? देश के करोड़ों अल्पसंख्यक ?

हरिद्वार की 'धर्म संसद' के तत्काल बाद एक बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ,न्यायविदों,

सेवानिवृत्त अफ़सरों, पूर्व सैन्य अधिकारियों ,आदि ने ऐसी चिंता व्यक्त करते हुए कि देश को गृह युद्ध की आग में धकेला जा रहा है अपील की थी कि पीएम को चुप्पी तोड़ना चाहिए । न तो पीएम ने चुप्पी तोड़ी और न ही संघ या भाजपा के किसी नेता ने देश में फैलाए जाने वाले सांप्रदायिक उन्माद की निंदा की। मणिपुर, हरियाणा और चलती ट्रेन में चुन-चुनकर यात्रियों की हत्या उसी मौन के नतीजे माने जा सकते हैं।

ट्रेन में हुए हत्याकांड को लेकर 'द वायर' द्वारा जारी एक खबर के अनुसार, सुपरफास्ट एक्सप्रेस के मुंबई पहुँचते ही एक भाजपा विधायक ने मीडिया से कहा कि घटना के कारणों की सघन तरीक़े से जाँच कर पता लगाया जाना चाहिए कि क्या आरपीएफ़ कांस्टेबल किसी तरह के अवसाद से पीड़ित या मानसिक रूप से विचलित था ? घटना की पुलिस द्वारा जाँच किए जाने के पहले ही विधायक ने कांस्टेबल की मानसिक अस्थिरता को हत्याकांड के संभावित कारण के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। खबरों के मुताबिक़, कांस्टेबल के परिवार-जन दावा कर रहे हैं कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है तथा पिछले छह महीनों से उसका उपचार चल रहा है।

सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर अस्वस्थ है तो (1) उसे यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेवा में क्यों तैनात किया गया ? (2) क्या कांस्टेबल के उच्चाधिकारियों को उसकी मानसिक बीमारी की जानकारी नहीं थी ?,(3) क्या मानसिक तौर पर विचलित/विक्षिप्त/बीमार व्यक्ति इस स्थिति में हो सकता है कि जिन यात्रियों को गोलियों का निशाना बनाना है उनका चयन वह चलती हुई ट्रेन की आठ बोगियों और पेंट्री कार में घूम कर कर सके ? क्या उसके हाथों मारे गये अल्पसंख्यक समुदाय के यात्री और तथा अंतिम व्यक्ति के शव के पास खड़े होकर दी गई 'हेट स्पीच' किसी संयोग अथवा मानसिक असंतुलन का परिणाम हो सकती है ?

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले सामूहिक हत्याकांडों/नरसंहारों के निष्कर्ष यही बताते हैं कि घटनाओं को अंजाम देने वाले हत्यारे निरपराध लोगों की भीड़ पर बेरहमी से गोलियाँ चलते हैं। हत्यारे न तो गोलियों का शिकार बनने वालों का उनके कपड़ों और शारीरिक प्रतीकों के आधार पर चुनाव करते हैं और न ही अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दर्शाने वाली कोई 'हेट स्पीच' देते हैं !

किसी व्यक्ति अगर को उसके द्वारा किए गए जघन्य अपराध में इस शंका का लाभ मिल सकता है कि वह गुस्सेल प्रकृति का है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो फिर लगातार तनावों और असुरक्षा में जीने वाली हुकूमतों को भी नागरिक उत्पीड़नों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। मणिपुर की घटना को भी उसी तरह के अपराध में शामिल किया जा सकता है !

सवाल सिर्फ़ तत्कालीन हुकूमतों का ही नहीं है ! नागरिकों की एक बड़ी आबादी भी कुछ तो व्यवस्था-जनित कारणों और कुछ निजी तनावों के चलते गहरे अवसाद और मानसिक बीमारियों की शिकार होती जा रही है। समाज में अपराध और आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं। क्या सामान्य नागरिक भी किसी एक मुक़ाम या अंग्रेज़ी में जिसे 'ट्रिगर' या 'टिपिंग पॉइंट' कहते हैं, पर पहुँचकर दूसरों की जानें लेना प्रारंभ कर देंगे या फिर उन इंतज़ामों पर यक़ीन करना बंद कर देंगे जिन्हें एक व्यवस्था के तहत सत्ताओं द्वारा सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है ? यह भी हो सकता है कि नागरिक घरों से बाहर निकालना ही बंद कर दें ! दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपनी ही राजनीतिक सुरक्षा में मशगूल सरकार को नागरिकों की बढ़ती असुरक्षा की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है !